21वीं सदी में वैश्विक आतंकवाद और भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियाँ

पीएच0डी0 उपाधि हेतु राजनीति विज्ञान विभाग, सामाजिक विज्ञान संकाय में पंजीयन हेतु

प्रस्तावित शोध प्रबंध सार

स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग
सामाजिक विज्ञान संकाय,

(2020)

बिनोद बिहारी महतो कोयलांचल विश्वविद्यालय,
धनबाद – 828130

शोध निर्देशिका
डॉ0 संजू कुमारी
एसोसिएट प्रोफेसर
राजनीति विज्ञान विभाग
बी0बी0एम0के0यू0, धनबाद (झारखण्ड)
Email- Id : sslntsanju@gmail.com

शोधार्थी
राजन राम
सहायक प्राध्यापक (अनुबंध)
राजनीति विज्ञान विभाग
चास महाविद्यालय, चास (बोकारो)
मो0 : 8210711816, 7870228257
Email- Id : response.rajan@gmail.com

अनुक्रमणिका

	अध्यायीकरण (Tentative Thesis Chapter Outline)	पृष्ठ सख्या
	प्रस्तावना	
	(क) शोध–समस्या	4–8
	(ख) साहित्य पुनरावलोकन	9
	(ग) शोध का उद्देश्य	10
	(घ) शोध परिकल्पना	10
	(ङ) शोध से संबंधित प्रश्न	11
	(च) शोध का महत्व एवं प्रासंगिकता	12
	(छ) शोध पद्धति	12
	अध्यायों का गठन	13–14
I	प्रथम अध्याय	
	बीसवीं सदी में वैश्विक आतंकवाद का स्वरूप	
II	द्वितीय अध्याय	
	इक्कीसवीं सदी में वैश्विक आतंकवाद का बदलता स्वरूप	
III	तृतीय अध्याय	
	इक्कीसवीं सदी में वैश्विक आतंकवाद और समकालीन राजनीति	
IV	चतुर्थ अध्याय	

	वैश्विक आतंकवाद का भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव	
V	पंचम अध्याय	
	वैश्विक आतंकवाद और भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियाँ	
VI	षष्ठ अध्याय	
	वैश्विक आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व के प्रमुख राष्ट्रों एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा	
VII	सप्तम अध्याय	
	भारतीय विदेश नीति की चुनौतियों से निपटने के रणनीतिक तरीके एवं सुझाव	
	उपसंहार	

शोध परियोजना प्रस्ताव

शोध समस्या का विवरण : हाल के वर्षों में समाचार पत्रों, सोशल मीडिया, इंटरनेट, टेलीविजन के साथ ही पूरे बौद्धिक जगत में वैश्विक आतंकवाद (Global Terrorism) चर्चा का विषय है कि इसकी शुरूआत कब और कैसे हुई और किन संगठनों के आतंक ने एक देश में फैले आतंकवाद की दहलीज लांघकर वैश्विक आतंकवाद का स्वरूप ग्रहण कर लिया है इस मुद्दे पर दुनियाभर के बुद्धिजीवी अनेक वर्षों से चिन्तन–मनन कर रहें हैं। यह एक लम्बी और कभी खत्म न होनेवाली बहस है।

आतंकवाद चाहे जिस किसी भी रूप में हो यह किसी राज्य की सीमा तक सीमित नहीं रह गया है, बल्कि यह एक वैश्विक चुनौती बन गया है। यदि यह किसी एक राज्य तक सीमित होता तो हमारा पड़ोसी देश पाकिस्तान रोज–रोज के धमाकों से यूँ न दहलता और अपने ही देश में ड्रोन से आतंकियों को नहीं मारता। आज आतंकवाद के रूप में वैश्विक आतंकवाद ने कई मुस्लिम देशों में शिक्षा व लोकतन्त्र का गला घोंट दिया गया है। आज इन देशों में शिक्षा व लोकतन्त्र का अभाव है। लोग अपने बीवी–बच्चों को लेकर जन्म भूमि से पलायन व विस्थापित होने को मजबूर है। आज विदेशों में मुस्लिमों पर शक किया जाता है। उन्हें एयरपोर्टों पर सुरक्षा के कड़े मानको से गुजरना पड़ता है। आज कई मुस्लिम देशों में विकास कार्य बाधित हैं। लोग खौफजदा हैं एवं डर के साये में अपने घरों में ही दुबककर कैदखाने जैसा महसूस कर रहें है। उन्हें अपने ही देश में गुलामों जैसा जीवन व्यतीत करना पड़ रहा है।(यादव, 2010 पृष्ठ 1–388)

विश्वयापी आतंकवाद का भारत ने कड़ी निन्दा की है, साथ ही संयुक्त राष्ट्र में शामिल सभी देशों से आतंकवाद को जड़ मूल से नष्ट करने की वकालत की है तथा इस तरह के 'आतंकवाद' को राष्ट के विकास में बाधक बताया है जिसे किसी भी राष्ट्र के द्वारा बर्दाश्त नहीं किया जा सकता और इससे निपटने के लिए वास्तविक एवं प्रभावी वैश्विक सहयोग की आवश्यकता है।

हाल के वर्षों में हम जिस संकट का सामना कर रहे हैं, उसका नाम है '**वैश्विक आतंकवाद**' और इसका स्तर बहुत ही खतरनाक है। आज विश्व में कोई भी देश चाहे वह कितना ही शक्तिशाली क्यों न हो, कितना ही ताकतवर या धनी क्यों न हो, इस खतरे से सुरक्षित नहीं है, और कोई भी लोकतांत्रिक राष्ट्र इसका समर्थन नहीं कर सकता। अपनी चाक–चौबंद सुरक्षा व्यवस्था पर इतराने वाला अमेरिका, फ्रांस, जर्मनी, इजरायल, ब्रिटेन, बेल्जियम एवं रूस आदि देश भी लगातार आतंकी हमले झेल रहा है। आतंकवाद की समस्या एक ऐसा मुद्दा है जो सम्पूर्ण विश्व की शांति और सुरक्षा के लिये एक गम्भीर संकट बना हुआ है और इसके फलस्वरूप हजारो लोगों को अपने प्राण गवाने पड़े हैं इसके साथ ही साथ इसने लाखों लोगों को अपने ही देश में शरणार्थी बनने पर विवश कर दिया है।(सहगल, 2004 पृष्ठ 1–232)

आज 'वैश्विक आतंकवाद' का जिस तरह से कुछ देशों द्वारा महिमामंडन किया जा रहा है और क्षुद्र स्वार्थों से वशीभूत होकर उसका समर्थन किया जा रहा है, उसे देखते हुए ऐसा नहीं लगता है कि उस पर घरेलू सुरक्षा शक्तियों या अपराध–निरोधी कार्यवाहियों या कड़े कानूनों के सहारे ही काबू पाया जा सकता है। विमानों के बलात् अपहरण की घटनायें, लार्ड हवाई अड्डे और म्यूनिख ओलम्पिक में हुए आक्रमण, नेपाल के अंतर्राष्टीय हवाई अडडे से भारतीय विमान आईसी–814 का अपहरण कर उसे अफगानिस्तान के कंधार में ले जाना और निर्दोष नागरिक बन्धकों के बदले में दुर्दान्त और खूंखार आंतकवादियों की रिहाई का मामला हो, चाहे यूरोपीय–अफ्रीकी या लैटिन अमेरिकी देशों यथा ब्राजील, अर्जेन्टीना और ग्वाटेमाला में अमेरिकी और अन्य राजनयिकों की हत्या, खारतूम, कारडोवा और बेरूत में आतंकवादी अपहरण एवं बंधक बनाने की घटनाओं और स्टाकहोम में जर्मन दूतावास पर कब्जा आतंकवादी कार्यवाहियों के ऐसे दृष्टान्त हैं, जिन्हें सरलता से विस्मृत नहीं किया जा सकता।

भारत ने आतंकवाद को बड़ी ही सहनशीलता के साथ झेला है। वर्तमान में आतंकवाद जो अब वैश्विक आतंकवाद का स्वरूप ग्रहण कर चुका है। मानव समाज के लिए एक चुनौती बन चुका है। भारत एक तरफ बढ़ती बेरोज़्ागारी, खाद्य समस्या, निम्न आर्थिक विकास की समस्या से जूझ रहा है तो दूसरी तरफ वैश्विक आतंकवाद की समस्या ने भारत की विदेश नीति–निर्माताओं के समक्ष अपने पड़ोसी देशों से संबंधों में संतुलन एवं समन्वय साधने की चुंनौती खड़ी की है।

भारत ने बड़ी ही दृढ़ता के साथ इस समस्या को विश्व पटल पर उठाया और इस बात की मांग की कि आतंकवाद की परिभाषा तय की जानी चाहिए। जैसा कि हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी ने संयुक्त राष्ट्र संघ के मंच से विश्व के नेताओं को संबोधित करते हुए कहा है **''आतंकवाद अच्छा या बुरा नहीं होता आतंकवाद सिर्फ आतंकवाद होता है''**।

आतंक के इस माहौल में दुनिया किस कदर जीने को विवश है यह हमें मिस्र के समुद्रतट पर देखने को मिला जब अयलान कुर्दी नामक एक बच्चा मिस्र के समुद्रतट पर मृत पाया गया।अयलान कुर्दी अपने पिता के साथ सीरिया से अप्रवास करने के दौरान उनका नाव डूब गया और उसका शव मिस्र के समुद्रतट पर आ पहुँचा। अयलान ने पूरी दुनिया को यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि आज हम किस तरह के वातावरण में जी रहे हैं। अभी हाल ही में पेरिस के स्टेडियम में हमले से कई सौ लोगों को अपनी जान से हाथ धोना पड़ा।

वैश्विक आतंकवाद का सबसे दुखद पहलू यह है कि आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई के लिए जब एकजुटता की बात आती है तो विश्व के ताकतवर देशों के अपने–अपने आर्थिक हित टकराते हैं जिससे वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई लड़ने का दावा खोखला नजर आता है। अमेरिका और रूस तथा यूरोपीय देशों का अलग–अलग नजरिया संयुक्त राष्ट्र के विभिन्न मंचों पर अक्सर देखने को मिलता है। क्या हमें यह मालूम नहीं कि किस तरह अमेरिका के द्वारा अफगानिस्तान में रूसी हस्तक्षेप से निपटने के लिए 'अलकायदा' के ओसामा बिन लादेन और 'तालिबान' इराक में 'आईएसआईएस' नामक जैसे संगठनों को शुरूआती दौर में

पाला पोसा नहीं गया ? शांति किसे नहीं चाहिए, लेकिन पश्चिमी शक्तियां जिनके जीडीपी का एक बड़ा भाग हथियारों के निर्यात से आता हो भला ऐसे आतंकरोधी अभियानों का हिस्सा बनना उन्हें क्यों मंजूर होगा। शांति और अमन–चैन के शत्रु जब किसी देश को अपना निशाना बनाते हैं, तो महाशक्तियों द्वारा उसे धैर्य और शांति बनाये रखने का उपदेश देती नजर आती है, लेकिन जब बात अपने ऊपर आती है तो ये एकजुट होकर पूरी दुनिया से इस आतंक के दावानल के समूल नाश का आह्वान करते नजर आते हैं। क्या इस तरह की एकतरफा शांति सम्भव है ?

तेज से गति से बढते आतंकवाद की प्रवृति पर रोक लगाने के लिए विश्व के महाशक्तियों से आभूषित राष्ट्रों द्वारा उठाये गये कदम भ्रामक प्रतीत हेाता है। जिसकी पुष्टि के लिए 'इंस्टीट्यूट फार इकोनामिकल एण्ड पीस' द्वारा वैश्विक आतंकवाद सूचकांक (जीटीआई) को अध्ययन के लिए लिया जा सकता है। जिसके अन्तर्गत आतंकवाद से प्रभावित देशों को अध्ययन के लिए चुना गया है। इसके प्रभावों और उससे निपटने के लिए वैश्विक रणनीतियों का विश्लेषण करें तो हमें पता चलता है कि इस संकट के खिलाफ दुनिया की महाशक्तियों ,द्वारा चलाये जा रहे अभियान में अन्तर्विरोध है। आस्ट्रेलिया की संस्था (इंस्टीट्यूट फार इकोनॉमिकल एण्ड पीस) द्वारा प्रकाशित रिर्पोट के अध्ययन से हमें निम्न जानकारिया मिलती है :–

- आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित दस देशों में पाकिस्तान के बाद भारत का स्थान छठवां है। हाल के वर्षों में जरूर इस मानक में कमी होकर अब सातवें स्थान पर आ गया है।
- आतंकवाद से सर्वाधिक प्रभावित शीर्ष पांच देशों में अफगानिस्तान, इराक, नाइजीरिया, सीरिया, और पाकिस्तान है।
- आतंकी वारदात की घटनाओं में होनेवाली मौतों में 1.2% के साथ यह संख्या 416 पहुंच गया है। विगत दशको में आतंकी हमलों में मौतों की यह सर्वाधिक संख्या है।
- मानवीय जीवन के नुकसान की बात करें तो दुनियाभर में 2014 के दौरान 32,658 से भी ज्यादा लोग आतंकवादी घटनाओं में मारे गए।
- इसके साथ ही अगर हम इन आतंकी हमलों से पूरे विश्व में होनेवाले आर्थिक नुकसान की बात करे तो 2014 में आतंकी घटनाओं के चलते जहाँ 52.9 अरब डॉलर का नुकसान दुनिया को उठाना पड़ा है। इससे कितने ही गरीब देशों में अनाज की कमी एव भूख की समस्या से निपटा जा सकता था। यह नुकसान पिछले साल के नुकसान 32.9 अरब डॉलर से 61 प्रतिशत अधिक है।

इस प्रकार इस अध्ययन का यह निष्कर्ष निकलता है कि पिछले 15 सालों में दुनिया भर में आतंकी घटनाओं की संख्या में वृद्धि हुई है और काफी जान–माल का नुकसान उठाना पड़ा है।

आज आतंकी घटनाओं के अनवरत समय से संचालित होने के कारण इसके स्वरूप में भी परिवर्तन हो रहा है। किसी भी तरह की आतंकी घटना हो, चाहे वह राज्य प्रायोजित आतंकवाद हो, सीमा पार आतंकवाद हो, मिलिट्री आतंक का भय हो लम्बे समय तक के लिए सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक और सांस्कृतिक क्षेत्रों में अपना प्रभाव किसी न किसी रूप में दिखलाती ही है। तात्कालिक नुकसान तो होते ही हैं, जिनमे मानवीय जीवन का नाश होता ही है, इस घटना का दीर्घकालिक मनोवैज्ञानिक प्रभाव के तहत लोगों में गम्भीर मानसिक बीमारी यथा अवसाद, कुण्ठा और जड़ता की स्थिति उत्पन्न हो जाती है। लोगों के बीच सामाजिक वैमनस्य बढ़ता है, भाई–चारे की भावना में कमी आती है, लोग एक दूसरे को संदेह की नजरों से देखते है, भय और गुस्से का माहौल उत्पन्न होता है। राजनीतिक प्रभाव का आकलन करें तो इससे प्रभावित देशों में अपने नागरिकों की सुरक्षा के लिए नियम कानून कठोर किए जाते हैं। वीजा प्राप्त करने के लिए नियमों में बदलाव किए जाते है और कड़े मानदण्ड स्थापित किए जाने से विभिन्न देशों के बीच रिश्तों पर संशय के बादल मंडराने लगते हैं। आर्थिक असर के रूप में निवेश की कमी से अर्थव्यवस्था को झटका लगाता है बेरोजगारी और हताशा की स्थिति उत्पन्न होती है। आतंकवाद के कारण विस्थापन और शरणार्थी की समस्या भी उत्पन्न हो जाती है। म्यांमार में रोहिंग्याओं और सीरिया से भागते मुस्लिम शरणार्थियों को उदाहरण के तौर पर लिया जा सकता है।

आज आतंक को संरक्षण एवं प्रोत्साहन देनेवाले सम्मिलित देशों में पाकिस्तान के अतिरिक्त चीन, अरब राष्ट्र तथा कुछ मध्य एशियाई देशों के साथ–साथ विश्व के विकासशील एवं विकसित सभी राष्ट्रों को यह सोचना होगा कि आतंकवाद सभी के लिए एक प्रमुख चिन्ता का विषय है। इसलिए यदि विश्व को सुरक्षित एवं भय के वातावरण से मुक्त रखना है तो सभी राष्ट्रों को आतंकवाद के खिलाफ एक साथ खड़ा होना होगा और एकजुटता के साथ इससे निपटना होगा।

वर्तमान वैश्विक परिदृश्य में विश्व के प्रमुख शक्तिशाली देश अपने वर्चस्व को कायम रखने के लिए समय–समय पर अपनी शक्तियों का प्रदर्शन करती रहती है जिसका सम्बन्ध आर्थिक एवं सैन्य शक्ति के साथ–साथ मानवीय और तकनीकी विकास से भी होता है। भारत एक विकासशील देश है और विकास के लिए अग्रसर है परन्तु अपनी घरेलू और विदेशी बाध्यताओं के कारण इनका मुकाबला अकेले करने की स्थिति में नहीं है। विदेश नीति पूर्ण रूप से परिवर्तनशील होता है। हर देश अथवा राष्ट्र अपनी क्षमता और राष्ट्रहित के अनुसार अपनी समस्याओं के निराकरण के लिए अपनी विदेश नीति में लगातार बदलाव करती रहती है, चूंकि राष्ट्रहित का मूल उद्देश्य राष्ट्रीय सुरक्षा और राष्ट्र की प्रगति है जिसके लिए भारत की विदेश नीति भी अपने राष्ट्रीय हितों के अनुरूप लगातार बदल रही है।

माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी के प्रधानमंत्री पद पर आसीन होने के उपरान्त भारतीय विदेश नीति का भी विस्तार तथा इसके स्वरूप में तेजी से परिवर्तन हो रहा है। किसी भी तरह का साम्राज्यवाद हो चाहे वह औपनिवेशिक साम्राज्यवाद हो या नव आर्थिक साम्राज्यवाद भारत हमेंशा से इसके विरोध में खड़ा रहा

है एवं शान्ति प्रिय राष्ट्र एवं विश्वबन्धुत्व का समर्थक रहा है। इन्हीं मूल्यों को कायम रखने के लिए भारत हमेशा से गुट–निरपेक्षता को स्थायित्व प्रदान करने के लिए राष्ट्र हित में सम्बन्धित प्रमुख शक्तिशाली देशों के साथ अपने सम्बन्धों को लगातार बढ़ावा दे रहा है।

चीन अपनी विस्तारवादी नीति के कारण भारत एवं अन्य राष्ट्रों का प्रतिद्वन्दी रहा है। अपनी इन्हीं नीतियों की वजह से वह आतंकवाद के प्रति ढुलमुल रवैया अपनाता रहा है और वैश्विक चिंताओं की अनदेखी करता रहा है। पाकिस्तान जो आतंक का गढ बन चुका है चीन उसे प्रश्रय देता रहा है और हरेक वैश्विक मंच पर उसका साथ निभाता रहा है और हर मुश्किल घड़ी में उसका दोस्त बना रहा है। विदेश नीति के मामले में भारत की सबसे बड़ी चुनौती केवल यह नहीं होगी कि वह अपने पड़ोसियों तथा तथा पूर्वी एशियाई देशों के संगठन आसियान एवं पश्चिम एशिया समेत विश्व की प्रमुख शक्तियों यथा अमेरिका, चीन, फ्रांस, ब्रिटेन, रूस तथा जापान एवं जर्मनी आदि देशों के साथ अपने संबंधों को सुदृढ करना भी चुनौती होगी क्योंकि वे शक्तियाँ अपना–अपना वर्चस्व कायम करने के लिए लगातार प्रतिस्पर्धा करती रहती है क्योंकि इन देशों के पास एक तरफ तो टेक्नोलॉजी की ताकत, धन–सम्पदा, उन्नत बौद्धिक संसाधन आदि है तो दूसरी ओर विशाल बाजार के रूप मे इनका बहुराष्ट्रीय नेटवर्क है। भारत को ऐसी भूमिका में आने के लिए लगातार प्रयास करते रहना होगा क्योंकि विशाल जनसंख्या के रूप में मानव संसाधन तो है इन्हें कार्यशील एवं बौद्धिक संसाधन के रूप में परिणत करना होगा, साथ ही रणनीतिक दृष्टि से अन्य उपायों को आजमाने का साहस दिखाना होगा।

वर्तमान भौगोलिक परिदृश्य में भारतीय विदेश नीति के सामने काफी चुनौतिय उठ खड़ी हुई है। विदेशी मोर्चे पर अत्यधिक चुनौतियाँ विद्यमान है। इन चुनौतियों में राजनीतिक, आर्थिक, ऊर्जा सुरक्षा एवं सामरिक चुनौती तथा शांतिपूर्ण संबंधो में समन्वय बनाने की चुनौती शामिल है :–

- पड़ोसी देशों यथा चीन, पाकिस्तान, बांग्लादेश, अफगानिस्तान, मालदीव, श्रीलंका, नेपाल आदि देशों से शांतिपूर्ण सम्बन्धों में निरन्तरता बनाये रखने और सन्तुलन साधने की चुनौती।
- चीन का प्रमुख शक्ति के रूप में उदय और भारत के पड़ोसी देशों को आर्थिक मदद के नाम पर उनका भूमि हड़प करने की नीति जिससे सीमा पर शांति बनाये रखने की चुनौती तथा पड़ोसी पाकिस्तान की आंतकवादी गतिविधियों को शह देना।
- ईरान परमाणु समझौते से पीछे हटना और अमेरिका द्वारा ईरान पर प्रतिबंध लगाने से भारत को अपनी ऊर्जा जरूरतों को पूरा करने के लिए ईरान से तेल ना खरीद पाना ।
- अमेरिका का अफगानिस्तान से निकलने की तैयारी करना, जिससे भारत में तालिबानी आतंकवादियों की घुसपैठ से निपटने की चुनौतियाँ।(पुरी 2017) और (कक्कड़ 2018)

साहित्य पुनर्विलोकन

(**सहगल**, 2016 पृष्ठ संख्या 1–232) ने अपने अध्ययन में तथ्यों के साथ पूरी दुनिया के मानव समुदाय को अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद के भयावह खतरे के प्रति अगाह किया है और इसके खिलाफ युद्ध की बड़ी ही कष्टकारी दृश्यों को प्रस्तुत किया है, युद्धों की बदलती प्रवृति को उजागर करते हुए आतंकवादी कृत्यों से संबंधित विषमता के तत्व से निपटने के संबंध में वह एक नया दृष्टिकोण प्रदान करते हैं और बताते हैं कि किस प्रकार आतंकी मंसूबो को ध्वस्त करने के लिए हमे कई वैकल्पिक और रणनीतिक उपायों की तलाश करने की आवश्यकता है। आतंकवादी संगठनों की विनाशकारी क्षमता एक चिन्ता का विषय है। इनकी वारदातों से उत्पन्न बदले की भावना राष्ट्रों के बीच युद्ध की आशंका को जन्म देती है और प्रतिद्वन्दी वातावरण का निर्माण होता है और देशों बीच युद्ध के बादल मंडराते रहते हैं।

(**कॉकबर्न**, 2016 पृष्ठ 1–157)**17** ख्याति प्राप्त अंतर्राष्ट्रीय पत्रकार ने अपनी पुस्तक में सीरिया और ईराक में अपने अस्तित्व के लिए लड़ रहे शिया, सुन्नियों, कुर्दों, अलावाइट और ईसाईयों के नारकीय एवं भयाक्रांत जीवन का सजीव चित्रण प्रस्तुत करते हुए इसलामिक स्टेट के आंतकियों के कुकर्मों का लेखा–जोखा प्रस्तुत करते हैं।

(**ग्लेटजर, केमफील्ड, मॉलर, तथा रोजाज** 2015 पृष्ठ 75–97)**18** ने अपने अध्ययन के एक अध्याय में निष्कर्ष निकाला है कि कैसे युद्ध और हिंसा के बीच जीवन की गुणवत्ता में गिरावट आती है। इसका विश्लेषण पुस्तक के एक अध्याय सदियों से युद्ध और हिंसा में किया है। इसमें युद्ध और हिंसा के सकारात्मक और नकारात्मक प्रभावों का विस्तार से विश्लेषण करके इसके आर्थिक, सामाजिक, राजनीतिक एवं मानवीय पक्षों को उजागर किया गया है।

(**सीकरी** 2017 पृष्ठ 1–298)**19** में लेखक ने अपने विश्लेषण में पाया है कि भारत की विदेश नीति रणनीतिक और नीति उन्मुख दृष्टिकोण से ढीली–ढाली है और भारत की विदेश नीति अपने पडोसी देशों की चुनौतियों से जूझ रही है । पड़ोसी देशो की आतंरिक राजनीति और भारत का विशाल आकार उन्हें शंकालु बना देता है। यह पुस्तक दीर्धकालिक उपायों और रणनीतियों का विश्लेषण करती है और बतलाती है कि भारत के तात्कालिक और रणनीतिक पड़ोस पर ध्यान केन्द्रित करते हुए हमें ऊर्जा सुरक्षा, आर्थिक कूटनीति, रक्षा और कूटनीति के बीच बातचीत को मजबूती और दृढ़ता से आगे बढ़ाना चाहिए।

उपर्युक्त अध्ययनों से पता चलता है कि वैश्विक आंतकवाद और भारत की विदेश नीति पर अलग–अलग कई अध्ययन और शोध हुए हैं परन्तु वैश्विक आतंक के परिप्रेक्ष्य में भारतीय विदेश नीति का अध्ययन बहुत ही कम हुआ है। प्रस्तुत शोध प्रस्ताव में वैश्विक आतंकवाद के प्रभावों का अध्ययन करते हुए भारतीय विदेश नीति के समक्ष कौन–कौन सी चुनौतियाँ उठ खड़ी हुई है और इन चुनौतियों से निपटने के लिए भारतीय नीति–निर्माताओं को किन–किन रणनीति को अपनाने की आवश्कता होगी इसका उपाय तलाशने की कोशिश इस शोध के द्वारा किये जाने की योजना है।

शोध विषय का प्रमुख उद्देश्य

आतंकवाद और भारतीय विदेश नीति जैसे विषय पर अलग–अलग कई शोध अनुसन्धान हुए हैं, परन्तु वर्तमान शताब्दी में जिस तरह आतंकवाद ने अपना दायरा बढाया है और उसके कारण इसने अपना नया स्वरूप ग्रहण कर लिया है यह किसी एक देश की समस्या नहीं रह गई है, बल्कि इसने वैश्विक चोला पहन कर अनेक राष्ट्रों के बीच गहन चिन्ता का विषय बन गया है। इस तरह के आतंकवाद ने भारत की विदेश नीति पर वर्तमान समय में किस तरह की चुनौतियां पेश की है, उसी पर आधारित हमारा शोध विषय **21वीं सदी में वैश्विक आतंकवाद और भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियाँ** के लिए निम्नलिखित उद्देश्य रखे गये हैं : –

वैश्विक आतंकवाद की समस्या का गहराई से अध्ययन कर आतंकवाद की भयावहता को दुनिया के सामने लाना है।

वैश्विक आतंकवाद ने भारतीय विदेश नीति के समक्ष किस तरह की चुनौतियाँ खड़ी की है, उनका विश्लेषणात्मक अध्ययन करना है।

वैश्विक आतंकवाद की समस्या पर चिंतन कर उसके प्रभाव का आकलन करना है।

इन वैश्विक चुनौतियों से निपटने के लिए रणनीतिक उपायों को खोज निकालना एवं उसका समाधान प्रस्तुत करना भी इस अध्ययन का एक प्रमुख उद्देश्य है।

उपर्युक्त उद्देश्यों को ध्यान में रखकर प्रस्तुत शोध परियोजना प्रस्ताव को तैयार किया गया है।

परिकल्पना

आज दुनिया तेजी से बदल रही है। तकनीक की उन्नति और बढते उपभोक्ता वर्ग की ताकत ने विभिन्न देशों के बीच व्यापार और व्यवसाय को बढ़ाने के लिए नए समीकरण तथा द्विपक्षीय सम्बन्धों को बढाने के लिए मजबूर किया है। आर्थिक गतिविधियों में बढोतरी तथा सेवा क्षेत्रों में खुलते नये अवसर से दुनिया बदलेगी। व्यापार और व्यवसाय ही वह कारक है जिससे दुनिया को वैश्विक आतंकवाद के लिए एकजुटता का नया रास्ता दिखलायेगी। जरूरत है तो बस अपने राष्ट्र के नागरिकों के मानवीय हितों को सुरक्षित रखने के लिए

दृढ प्रतिज्ञ होकर सोचने की। भारत को घरेलू और विदेशी जरूरतों और अपने पड़ोसी देशों के हितों का सम्मान करते हुए नये मोर्चे खोलने होंगे। इनमें शामिल है व्यापार, सौर–ऊर्जा, घरेलू ईंधन की सुरक्षा, ऊर्जा सुरक्षा, पर्यावरण की सुरक्षा, कृषि में नये तकनीकों का प्रयोग और विशेष रूप से संचार क्षेत्र में नयी तकनीक का प्रयोग । इन मुद्दों पर भारत विश्व के प्रमुख शक्तियों के बीच एक नया खिलाड़ी बनने की क्षमता रखता है। वैश्विक आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई,में ये ऐसे तत्व है जिनका प्रयोग भारत कर सकता है। पाकिस्तानी आतंकवाद से निपटने के लिए व्यापक और सार्थक अंतर्राष्ट्रीय गठबंधन और सकारात्मक सहयोग जरूरी है तो दूसरी ओर भारतीय विदेश नीति को सशक्त और प्रभावी बनाने की जरूरत है।

मोटे तौर पर शोध विषय **21वीं सदी में वैश्विक आतंकवाद और भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियाँ** शोध विषय के लिए निम्नलिखित परिकल्पनाएँ गढ़ी गई है :–

- वैश्विक आतंकवाद भारत, मध्य एशिया, यूरोप, अमेरिका समेत पूरे विश्व के लिए एक बड़ा खतरा रहा है।
- वैश्विक आतंकवाद के बढते प्रसार ने भारत की विदेश नीति के समक्ष राजनीतिक, आर्थिक, सामाजिक, सामरिक और ऊर्जा सुरक्षा की चुनौतियाँ खड़ी की है।
- सीरिया में आईएसआईएस, मध्य एशियाई देशों में अलकायदा और उसकी विभिन्न शाखाओं तथा कट्टरपंथी इस्लामी समूहों ने वैमनस्य, हिंसा को बढाया है एवं विभिन्न देशों के बीच भाई–चारे में कमी की है। इनके खिलाफ लड़ाई विशेष रूप से पश्चिमी एशियाई देशों के साथ खुफिया जानकारियों का आदान–प्रदान तथा सहयोग के जरिए इनकी कारवाईयों पर नकेल कसी जा सकती है।
- कारोबार से ज्यादा समझ आने वाली कोई भाषा नहीं। अतः सख्त आर्थिक रिश्ते, ज्यादा–से–ज्यादा देशों के साथ कूटनीतिक संबंधों की मजबूती ही भारतीय विदेश की चुनौतियों से निपटने की राह आसान बना सकती है।

शोध विषय से संबंधित प्रश्न

21वीं सदी में वैश्विक आतंकवाद और भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियाँ शोध समस्या जब मेरे अन्तर्मन में आया तो कई ऐसे विचारणीय प्रश्न उभर आए जिनका जबाब मैं इस शोध के द्वारा ढूंढना चाहता हूँ, जो कि इस प्रकार है :–

1. वैश्विक आतंकवाद आखिर है क्या ? और इसका स्वरूप कैसा है ?

2. क्यों दुनिया इस गम्भीर समस्या पर अपने राजनीतिक हित को देखते हुए इसे अच्छे और बुरे आतंकवाद के रूप में देखने की कोशिश करते हैं ?
3. दुनिया के प्रमुख देश इस गम्भीर समस्या पर एकजुट क्यों नहीं हो पा रहे हैं ?
4. कहीं इसका कारण हथियारों का एक बड़ा बाजार तो नहीं हैं ?
5. क्या मानवता से बढ़कर हथियारों का व्यवसाय एकमात्र हित रह गया है ?
6. भारत के नीति नियंता इस गम्भीर खतरे पर कैसा दृष्टिकोण रखते हैं और वे इस खतरे को किस रूप में लेते हैं ?
7. वैश्विक आतंकवाद से निपटने के लिए वर्तमान सरकार किस प्रकार की रणनीति अपनायेगी ?

शोध विषय का महत्व एवं प्रासंगिकता

भारत लम्बे समय से वैश्विक आतंकवाद का शिकार रहा है। भारत के आंतरिक हिस्से जम्मू–कश्मीर, पंजाब, नागालैण्ड, मणिपुर, असम, त्रिपुरा जैसे राज्य कई प्रकार के आतंकवादियों जैसे पाकिस्तानी, बांग्लादेशी, खालिस्तानी, माओवादियों से पीड़ित रहा है। इन राज्यों की सुरक्षा में लगे हजारों सैनिकों और जवानों ने अपनी शहादतें दी है तो दूसरी ओर हजारों निर्दोष नागरिकों की जाने ली हैं। राज्य का बेशकीमती संसाधन नागरिकों के जान–माल की सुरक्षा में खर्च करना पड़ा है। यदि आतंकवाद का भय न होता तो इन पर खर्च होनेवाली राशि का उपयोग विकास कार्यों पर किया जा सकता था। अकेले जम्मू–कश्मीर की सुरक्षा के लिए केन्द्र एवं राज्य सरकार को औसतन पाँच करोड़ प्रतिदिन (अनुमानित) खर्च करना पड़ रहा है।

आतंकवाद ने अपनी सीमा लांघते हुए वैश्विक आतंकवाद का स्वरूप ग्रहण कर लिया है और अब यह दो देशों की समस्या न होकर वैश्विक समस्या बन गया है जो कि पूरे विश्व शांति के लिए चिंता का विषय है। अतः समय रहते इस पर काबू नहीं पाया गया तो आनेवाली नस्लें मानव समुदाय को माफ नहीं करेगी। यदि समय रहते इस वैश्विक समस्या पर गम्भीरतापूर्वक विचार किया जाय और मिलजुलकर इस समस्या का डटकर सामना किया जाए तो इस समस्या पर काबू पाया जा सकता है। यदि हिटलर और औसामा का अंत किया जा सकता है तो आईएसएस, बोको हरम, हूजी, तालिबान जैसे सैकड़ों दुर्दांत मानवता के दुश्मन संगठनों का भी अंत किया जा सकता है, जरूरत है तो सिर्फ विश्व समुदाय को एकजुट होकर, निष्पक्ष और तात्कालिक हितों को तिलांजली देकर इस समस्या पर पुनर्विचार करने की।

अध्ययन क्षेत्र, शोध पद्धति एवं स्वरूप

अध्ययन क्षेत्र – यह अध्ययन भारतीय विदेश नीति के परिप्रेक्ष्य में वैश्विक आतंकवाद की समस्या पर अध्ययन किया जाएगा।

शोध पद्धति एवं स्वरूप – हमारे अध्ययन का स्वरूप वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक होगा। चूंकि हमारे अध्ययन का विषय समकालीन विश्व वैश्विक आंतकवाद की घटनाओं का प्रभाव भारतीय विदेश नीति पर पड़ने वाले

प्रभावों पर आधारित है। अतः हमने अपने अध्ययन में वर्णनात्मक एवं विश्लेषणात्मक विधि का सहारा लेने का निश्चय किया है।

ऐतिहासिक विधि :– यह वह विधि है जिसके द्वारा वर्तमान काल में घटित होने वाली घटनाओं को अतीत में घटित घटनाओं के क्रमिक विकास की एक कड़ी के रूप में देखकर उनका अध्ययन किया जाता है। प्रस्तुत शोष हेतु देश–विदेश से प्रसारित होनेवाली पत्र–पत्रिकाएँ, मीडिया रिपोर्टो, भारत सरकार एवं भारतीय विदेश संस्थान द्वारा प्रकाशित दस्तावेजों, मीडिया रिपोर्टों, पत्र–पत्रिकाओं, एवं प्रतिष्ठित लेखकों की पुस्तकों/रचनाओं, भाषणों, व्याख्यानों, एवं पत्रकारों के आलेख, आतंकवाद की समस्या पर होनेवाले राष्ट्रीय एवं अंतराष्ट्रीय स्तर पर होनेवाले सेमिनारों में होनेवाली चर्चाओं आदि का अध्ययन कर किया जाएगा।

तुलनात्मक पद्धति या विश्लेषण :– जब हम विभिन्न सामाजिक घटनाओं के बीच पायी जाने वाली समानताओ ं या असमानताओ की तुलना करके कमबद्ध और व्यवस्थित रूप से कोई सामान्य निष्कर्ष प्रदान करते हैं तो अध्ययन की इस पद्धति को तुलनात्मक पद्धति या विश्लेषण कहते हैं। प्रस्तुत शोध में तथ्यों एवं घटनाओं का तुलनात्मक विश्लेषण कर उनकी व्याख्या की जाएगी तत्पश्चात किसी सामान्य निष्कर्ष निकालने की कोशिश की जाएगी।

प्राथमिक स्रोतों में अंतर्राष्ट्रीय जगत में वैश्विक आतंकवाद की घटनाओं के आंकड़ें मीडिया रिपोर्टों, समाचार पत्रों व अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार संगठनों द्वारा जारी आंकड़ों, प्रकाशित पुस्तको, पत्र–पत्रिकाओं व भारतीय विदेश संस्थान तथा अन्य संस्थानों जैसे अंतर्राष्ट्रीय आर्थिक शांति संगठन से प्राप्त रिपोर्टों का संकलन किया जायेगा।

द्वितीयक स्रोतों में वैश्विक आतंकवाद से जुड़ी पुस्तकों, शोध पत्रो, अन्तर्राष्ट्रीय लेवल पर प्रकाशित जर्नल, अखबार, मैगजीन आदि का अध्ययन व विश्लेषण कर किया जायेगा।

अध्यायों का गठन

अध्यायों का गठन – सम्पूर्ण शोध पुस्तिका को आठ अध्यायों में विभक्त करने का प्रस्ताव है जो इस प्रकार होगा :–

प्रस्तावना

(क) शोध–समस्या

(ख) शोध का उद्देश्य

(ग) शोध परिकल्पना

(घ) साहित्य पुनरावलोकन

(ड़) शोध से संबंधित प्रश्न

(च) शोध का महत्व एवं प्रासंगिकता

(छ) शोध पद्धति

प्रथम अध्याय

बीसवीं सदी में वैश्विक आतंकवाद का स्वरूप

द्वितीय अध्याय

इक्कीसवीं सदी में वैश्विक आतंकवाद का बदलता स्वरूप

तृतीय अध्याय

इक्कीसवीं सदी में वैश्विक आतंकवाद और समकालीन राजनीति

चतुर्थ अध्याय

वैश्विक आतंकवाद का भारतीय विदेश नीति पर प्रभाव

पंचम अध्याय

वैश्विक आतंकवाद और भारत की विदेश नीति के समक्ष चुनौतियाँ

षष्ठ अध्याय

वैश्विक आतंकवाद की चुनौतियों से निपटने के लिए विश्व के प्रमुख राष्ट्रों एवं संयुक्त राष्ट्र द्वारा उठाए गए कदमों की चर्चा

सप्तम अध्याय

भारतीय विदेश नीति की चुनौतियों से निपटने के रणनीतिक तरीके एवं सुझाव

उपसंहार

संदर्भ स्रोत

सहायक पुस्तकें / पत्र–पत्रिकाएँ / जर्नल्स / समाचार पत्र

इन्टरनेट से चुनिंदा आलेख

इस प्रकार प्रस्तुत शोध प्रबंध में वैश्विक आतंकवाद से उत्पन्न चुनौतियों को भारत की विदेश नीति के संदर्भ में अध्ययन एवं विश्लेषण कर विश्व शांति की दिशा में क्या–क्या प्रयास किए जा सकते हैं, उसके लिए सुझाव तलाशने की भी योजना प्रस्ताव है।